Manufacture of Colour T.V. Components

2977. SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether the Department of Electronics has made a proposal for the manufacture of important components of colour TV;

(b) if so, the actual cost involved in manufacturing the same;

(c) whether Government have decided to manufacture these components in India; and

(d) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M. S. SANJEEVI RAO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). There is a project approved and Letter of Intent issued for the manufacture of colour TV picture tubes in the State of Punjab. This involves a total outlay of about Rs. 40 crores. The capacity will be 4 lakhs colour TV picture tubes per year. Details of know-how and plant are still being finalised.

नई तकनीकी तथा वैज्ञानिक नीति तैयार करना

2978. **श्री चतुर्भुज :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की परिस्थितियों के अनुसार कोई नई तकनीकी तथा वैज्ञानिक नीति तैयार की गई है ताकि प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच समन्वय हो सके तथा विचारों का आदान प्रदान हो सके और विश्व भर की प्रौद्योगिकी की रफ्तार को देखते हुए देश की आवश्यकताओं को यथा-सम्भव शीघ्र पूरा किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समर्थन के प्रति प्रतिबद्ध है जैसाकि 1958 में सरकार द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक नीति संकल्प में परिकल्पना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए तथा देश के लिए महत्वपूर्ण अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के समर्थन में छठी योजना के दौरान अत्यधिक पूंजी निवेश भी किया जा रहा है। छठी योजना अवधि के लिए अनुसन्धान तथा विकास में कुल पूंजी-निवेश 3367 करोड़ रुपये का है।

नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कार्पोरेशन (एन० आर० डी० सी०) को अनुसन्धान प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए उन्नत कार्य को उद्योगों के माध्यम से वास्तविक उपयोग को हाथ में लेने का कार्य सौंपा गया है। 1000 से भी अधिक ऐसे डिजाइनों और प्रक्रियाओं को एन० आर० डी० सी० द्वारा हाथ में लिया गया है और 400 से भी अधिक वस्तुओं को औद्योगिक एककों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और इसी प्रकार के अन्य कार्य किये जा रहे हैं। प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच के ये सम्पर्क कई वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यमों से और आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उद्योग, विश्वविद्यालयों और सरकारी प्रयोगशालाओं में

अनुसंधान कार्य को प्रायोजित कर सकते हैं जिसके लिए खर्च किये हुए वास्तविक व्यय के 133 प्रतिशत राशि की कर से पूर्व आय से कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है। उद्योगों के लिए अपने-अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए भी और प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें अनुसंधान तथा विकास पर किये गये व्यय को 100 प्रतिशत बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था है। अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति में व्यय के 125 प्रतिशत भाग को बट्टेखाते में डाला जा सकता है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रतिष्ठापित संयंत्रों और मशीनरी पर 35% तक की संवर्धित पूंजी निवेश की छूट के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। ऊर्जा की बचत करने वाली स्कीमों में भी विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं। यह सुखद विषय है कि इन उत्साहवर्द्धक स्कीमों के परिणामस्वरूप, अनुसंधान तथा विकास के लिए मान्यताप्राप्त औद्योगिक एककों की संख्या 1975 की 250 से बढ़कर अब 750 से भी ऊपर हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसंधान को बढ़ाने की अपनी स्कीम के माध्यम से, प्रौद्योगिकी विकास के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के साथ-साथ औद्योगिक एककों को भी अनुदान दिए हैं। अधिक महत्व वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की एक स्कीम भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई है। आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में पूंजी निवेशों में और सुधार लाने के विचार से, भारत सरकार के मंत्रालयों में वैज्ञानिक सलाहकारों को नियुक्त करने की सम्भावना का पता चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की अनुसंधान सलाहकार परिषदों में विभिन्न उद्योगों से लिए गए सदस्य शामिल हैं ताकि विचारों का उचित आदान प्रदान हो सके तथा उद्योग के लिए उपयोगी अनुसंधान परियोजनाओं का निर्माण हो सके और परिणामों के अनुप्रयोग के लिए बाद में स्थानान्तरण हो सके। सरकार, उत्पादन के लिए प्रयोगशालाओं में प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण में तथा आयातित प्रौद्योगिकी को आत्मसात किये जाने में भी इन्जीनियरी और परामर्शदाता संगठनों को सम्बद्ध करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने तथा उसके अनुकूलन करने की एक स्कीम भी अभी अनुमोदित की गई है, ताकि प्रौद्योगिकी के आत्मसात और अपग्रेड करने का तंत्र स्थापित किया जा सके। कुछ मामलों में, सरकार ने अधिक महत्व के क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुविधाएं स्थापित करने का उपक्रम किया है। एन० आर० डी० सी० भी उद्योगों की विकास परियोजनाओं का वित्तीयन कर रहा है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग का गठन 1981 में किया गया और अब यह देश में सौर ऊर्जा तथा जैव भार के उपयोग के लिए परियोजनाओं को समर्थन प्रदान कर रहा है।

उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिसमें इलेक्ट्रानिकी, अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा शामिल है, विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य प्रयोगशालाओं के लिए उपयोगी स्कीमों के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है तथा उद्योगों द्वारा संघटकों के उत्पादक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।